Centre for Research & Dialogue

A Trust dedicated for sustainable development of Bihar

Registration number- 19, Address- 306, Tara Towers, North Shastri Nagar, Patna- 800023

M- 9779127097, 7717768938

चमकी बुखार निगरानी अभियान की पहली रिपोर्ट

जमीनी शोध- सेंटर फॉर रिसर्च एंड डायलॉग, पटना

41% मैनपावर से कैसे चमकी का मुकाबला करेंगे मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल

- डॉक्टरों-स्वास्थ्य कर्मियों के अत्यधिक कमी है मुजफ्फरपुर के सर्वाधिक चमकी प्रभावित पांच प्रखंडों के सरकारी अस्पतालों में
- 88 की जगह सिर्फ 27 एलोपैथिक चिकित्सक हैं कार्यरत
- ए ग्रेड नर्सों के सभी 114 पद रिक्त
- मीनापुर के सभी सात अतिरिक्त पीएचसी में कोई डॉक्टर नहीं
- चमकी बुखार को लेकर काम करने वाली संस्था सीआरडी के शोध से हुआ खुलासा
- पिछले साल जागरूकता और सर्वेक्षण का काम करने वाली संस्था इस साल करेगी सरकारी प्रयासों की निगरानी

पृष्ठभूमि-

मुजफ्फरपुर और आसपास के आधा दर्जन जिले में हर साल गर्मियों में एईएस(चमकी) बुखार सैकड़ों बच्चों को अपने चपेट में ले लेती है. पिछले साल भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 615 बच्चे इस

रोग से पीड़ित हुए, जिनमें 180 से अधिक बच्चों की मौत हो गयी. मुजफ्फरपुर के प्रखंड बोचहां, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर और मुशहरी में इस रोग का कहर सबसे अधिक देखा गया है. सरकार भी इस साल इन प्रखंडों पर विशेष ध्यान देकर अपनी तैयारी कर रही है. मगर इस पांच प्रखंडों में सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या इस रोग के मुकाबले के लायक है, यह देखना जरूरी है. यही जानने के मकसद से हमने यह जमीनी शोध किया है.

यह शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले साल जब चमकी बुखार से यहां बच्चों की मौत हो रही थी, उस वक्त बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि हमारे पास स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 57 फीसदी और नर्सों के 71 फीसदी पद रिक्त हैं. तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि यह काम तो आपका है, आप इसकी भरपाई करें. ऐसे में हम यह भी समझना चाहते थे कि आखिर पिछले सात-आठ महीनों में सरकार ने इस बैकलॉग को भरने की दिशा में क्या-क्या काम किया.

सरकारी अस्पतालों की संख्या

इन पांचों प्रखंडों में हालिया सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 5 प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 38 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत स्तर पर कार्यरत 252 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत हैं. मगर इनमें अभी 5 प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और 181 स्वास्थ्य उपकेंद्र ही संचालित हैं.

एलोपैथिक डॉक्टर

इन प्रखंडों के सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) और एपीएचसी (एडीशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर) में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद क्रमशः 35 और 53 हैं. यानी इन पांच प्रखंडों के दोनों तरह के सरकारी अस्पतालों में कुल 88 एलोपैथिक डॉक्टर होने चाहिए. मगर अब तक के लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन अस्पतालों में कार्यरत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 14 और 13 हैं, यानी कुल 27. संक्षेप में समझें तो जहां 88 एलोपैथिक डॉक्टरों के पद स्वीकृत थे, वहां सिर्फ 27 डॉक्टर कार्यरत हैं.

मीनापुर के सभी सात अतिरिक्त पीएचसी बिना किसी डॉक्टर के चल रहे हैं. जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मीनापुर प्रखंड में पिछले साल 70 से अधिक बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित हुए थे.

इन पांचों प्रखंडों में कुल 31 ऐसे सरकारी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां डॉक्टर होने चाहिए थे, मगर इन 31 अस्पतालों के संचालन के लिए सिर्फ 27 डॉक्टर सरकार ने उपलब्ध कराये हैं.

आयुष चिकित्सक

इन पांच प्रखंडों के 31 अस्पतालों में 29 आयुष चिकित्सक होने चाहिए थे, मगर सिर्फ 17 पदस्थापित हैं.

ए ग्रेड नर्स

इन पांचों प्रखंडों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 64 रेगुलर और 50 संविदा वाले, यानी कुल 114 ए ग्रेड नर्सों के पद स्वीकृत हैं. मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी 114 ए ग्रेड नर्सों के पद पर एक भी नर्स कार्यरत नहीं हैं. यानी सारे पद खाली हैं.

एएनएम

एएनएम के कुल 266 स्थायी और 178 ठेके वाले पद, यानी कुल 444 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 257 पदों पर ही एएनएम कार्यरत हैं. ठेके वाले 178 पदों के लिए सिर्फ 9 की पदस्थापना है.

फार्मासिस्ट

कुल 31 पद स्वीकृत हैं, सिर्फ 6 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं.

लेबोरेटोरी टेक्नीशियन

कुल 46 पद स्वीकृत थे, सिर्फ 10 स्टाफ कार्यरत हैं. आप समझिये कि 31 अस्पतालों में से संभवतः 21 में कोई टेक्नीशियन नहीं है, जहां अगर कोई चमकी बुखार पीड़ित बच्चा पहुंच जाये तो उसकी बीमारी की जांच हो सके.

ड्रेसर

कुल 26 पद स्वीकृत हैं.इस इलाके के 31 अस्पतालों में से सिर्फ एक ही में ड्रेसर हैं.

मानव संसाधन का फर्क

इस तरह देखें तो इन पांच प्रखंडों में सामान्य रूप से जो कुल 778 चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के पद स्वीकृत हैं, उनमें से अभी सिर्फ 318 लोग कार्यरत हैं. यानी इन पांच प्रखंडों में हम स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि सिर्फ 40.87 फीसदी मानवीय संसाधन से कर रहे हैं. यह बड़ा गैप है. इनमें अगर सिर्फ डॉक्टरों की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 30.68 फीसदी रह जाता है. एएनएम की संख्या जरूर अधिक है, मगर हमें ध्यान रखना होगा कि इनकी बड़ी संख्या 257 में से 181 टीकाकरण के काम में लगी रहती हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में हमें 31 अस्पतालों में सिर्फ 76 एएनएम से

ही काम चलाना पड़ेगा. ए ग्रेड नर्स के तो सभी 114 पद खाली ही हैं. लैब टैक्नीशियन जो चमकी बुखार की जांच के लिए जरूरी आदमी है, उसके लगभग 78 फीसदी पद खाली हैं.

इस लिहाज से देखें तो पिछले साल जुलाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े पेश किये थे, अभी चमकी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित इन प्रखंडों में स्थिति उससे भी अधिक गंभीर है. ऐसे में यह सवाल सहज है कि इस बार स्वास्थ्य विभाग इन इलाकों में किस आधार पर चमकी बुखार का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है.

क्यों इन पांच प्रखंडों पर है फोकस-

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन पांच प्रखंडों में पिछले साल(2019) में कुल 278 बच्चे चमकी बुखार की चपेट में आये. इनमें से 58 बच्चों की मौत हो गयी. इन प्रखंडों में चमकी बुखार से पीड़ित हुए बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 45.2 फीसदी है.

हमारी मांग

या तो जल्द से जल्द इन रिक्त पदों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाये या कम से कम चमकी बुखार के मौसम में दूसरे इलाकों से तीन-चार महीने के लिए कर्मियों को डेपुटेशन पर भेजा जाये.

क्या है हमारा चमकी बुखार निगरानी अभियान-

इस साल सरकार से लेकर विभिन्न संस्थाएं चमकी बुखार के दुहराव को रोकने के अभियान में जुटी है. हमारा निगरानी अभियान इस दौरान किये जा रहे सरकारी प्रयासों की निगरानी करेगा. वह देखेगा कि पटना और मुजफ्फरपुर में जो योजनाएं बन रही हैं, वे जमीन पर कितनी उतर रही हैं? इस तरह हम अभी से जून तक सतत निगरानी करते हुए सरकार और समाज को जमीनी स्थिति बतायेंगे. यह सरकार के लिए फीड बैक की तरह भी हो सकता है.

शोध कर्ता- संजीत भारती, शोध विश्लेषण- पुष्यमित्र